The death of Pope John Paul II, once more, exposed the shaky, double-standard secularism as practiced by the Indian state. By rushing to declare a 3-days state mourning for the late Pope, the self-styled "secular" Indian state showed how flawed its version of secularism is.

Is a secular state really right in mourning a religious leader? More so because this same self-proclaimed "secular" state never bothered to officially mourn any deceased head of any Indian religion. A large official delegation was sent to Rome to represent India at the funeral. But this same Indian state has never bothered to be officially present, when any head of an Indian religion had died. Worse, never did the Vatican bother to show such reverence to any Indian religion or any head of the Indian state and/or government.

This paper argues that a modern and secular nation-state must keep away from indulging in appeasement politics and should strictly separate official matters from those of private issues, that a religion undoubtedly is. The state must follow a policy of equvi-distance to all religions. A one-sided appeasement of minorities – as indeed that of the majority – can only be counter-productive in the long run.

पोप की मृत्यु पर भारत में राष्ट्रीय शोक

धर्मनिरपेक्षता के नाम पर भौंडा मज़ाक !

- रजनीश तिवारी

भारतीय संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है - एक ऐसा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र जिसमें सभी धर्म के मानने वालों को समान अधिकार होंगे, जिसमें किसी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा। सवाल उठता है कि क्या यह वास्तव में हो रहा है? इस प्रश्न के उठने की वजह यह है कि भारत के तमाम स्वघोषित बुद्धिजीवी, अंग्रेज़ी भाषाई मीडिया, राजनेता, यहाँ तक कि बॉलीवुड के तमाम फ़िल्म निर्देशक भी भारत में धर्मनिरपेक्षता पर निरंतर हो रहे कथित हमलों को लेकर मगरमच्छी आँसू बहा-बहा कर ऐसी धारणा फैला रहे हैं जैसे कि भारत में अल्पसँख्यकों की जान पर बनी पड़ी है और 'साम्प्रदायिक, कट्टर' हिंदू भारी सँख्या में अल्पसँख्यकों की दुर्दशा करने को बेताब हैं।

समय आ गया है कि ऐसे मुद्दों पर विचार किया जाये और इसके कारणों की समीक्षा की जाये। क्या भारत में अल्पसँख्यक सचमुच किसी ऐसे खतरे का सामना कर रहे हैं, जिसकी वजह उनका धर्म है? रोज़मर्रा के अपराध - जैसे कि चोरी,

डाके, हत्यायें या बलात्कार - यह अपराध हर समाज में होते हैं और उनके उन्मूलन का प्रयत्न करना सरकार का कर्तव्य है। लेकिन इन अपराधों का कोई लेना-देना इनके शिकारों के धर्म से नहीं बल्कि देश की कानून व्यवस्था से है। यदि यह अपराध हो रहे हैं तो उनसे सिर्फ़ अल्पसँख्यक ही नहीं बल्कि बहुसँख्यक भी समान तरह से त्रस्त हैं। यह कौन सा गणित है कि यदि एक बहुसँख्यक के घर में चोरी हो तो वह चोरी और अल्पसँख्यक के घर में हो तो वह धार्मिक प्रताड़ना? ऐसा कह-कह कर हम सिर्फ़ अल्पसँख्यकों के मन में भय और अलगाव और बहुसँख्यकों के मन में प्रतिरोध पैदा करते हैं।

उपरोक्त अपराधों की जड़ में अपराधी के चरित्र के अलावा संभवतः गरीबी, अशिक्षा और देश में व्याप्त भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा हाथ है। लेकिन इनमें धर्म को घसीटने का न तो कोई कारण है और न ही औचित्य। और यदि कोई व्यक्ति कभी धर्म के नाम पर ऐसे घिनौने कार्य करे भी, तो उसे स्वभावतः उसकी कठोर सज़ा मिलनी चाहिये।

लेकिन धर्मनिरपेक्षता के स्वघोषित ठेकेदार क्या कभी अपने गिरेबान में भी झाँक कर देखते हैं? अभी हाल का ही वाकया लें - कैथोलिक संप्रदाय के प्रमुख पोप जॉन पॉल द्वितीय की मृत्यु पर भारत सरकार ने फटाफट तीन दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया। सरकारी बाबुओं और उनके राजनैतिक आकाओं को यह भी खयाल नहीं आया कि उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति भारत आने वाले थे और राष्ट्रीय शोक के वक़्त राजकीय मेहमानों का स्वागत नहीं किया जाता। इसलिये पोप जैसे धर्मगुरु की मौत पर घड़ियाली आँसू बहा रही धर्मनिरपेक्ष सरकार ने इसका खयाल आने पर उज्बेकिस्तान सरकार से विनती की कि उनके राष्ट्रपति अपनी यात्रा कुछ दिनों के लिये स्थगित कर दें। उनके न मानने पर भारत सरकार ने अपनी 'बुद्धिमत्ता' का हास्यास्पद परिचय देते हुये राष्ट्रीय शोक में छुट्टी की घोषणा करके उसे दो भागों में बाँट दिया। यदि यह मामला इतना ग़मगीन न होता तो इसको लेकर हँसना पड़ता। पर हमारे महान धर्मनिरपेक्षी जो न करें वही कम है।

निश्चय ही कोई भी मृत्यु अपने आप में एक दुखद घटना है, क्योंकि एक मनुष्य अब कम से कम उसके शारीरिक रूप में दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। और फिर पोप तो एक विश्व विख्यात व्यक्ति थे। उनकी मृत्यु पर निश्चय ही सरकार को

अपनी संवेदना प्रकट करनी चाहिये थी।

लेकिन एक धर्मगुरु की मौत पर एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र शोक मनाये और झंडे को नीचा करे, यह समझ में नहीं आता। और यदि मनाये भी तो फिर क्या यह नियम सिर्फ़ ईसाई धर्मगुरुओं के लिये लागू होता है? मुझे नहीं याद है कि कभी किसी शंकराचार्य, किसी इमाम या किसी सिख गुरु की मृत्यु पर भारत सरकार ने राष्ट्रीय शोक घोषित किया हो। लगता है भारत सरकार को शोक तभी होता है, जब मरने वाले के पास विदेशी पासपोर्ट हो।

हो सकता है हमारे स्वघोषित धर्मनिरपेक्षी कहें कि पोप सिर्फ़ एक धर्मगुरु नहीं बल्कि वैटिकन के राष्ट्र प्रमुख भी थे, जिसे एक स्वतंत्र देश का दर्जा प्राप्त है। मगर तब सवाल उठता है क्या वैटिकन ने भारत के किसी राष्ट्र प्रमुख की मृत्यु पर कभी राष्ट्रीय शोक घोषित किया है? इंदिरा गांधी की मृत्यु उनके प्रधानमंत्री रहते हुई, वैसे ही जवाहर लाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री पद पर रहते हुये स्वर्गावासी हुये। क्या कभी वैटिकन ने राष्ट्रीय शोक ज़ाहिर किया या अपना कोई दूत भारत भेजा मृतक के अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिये? ज़ाहिर है - नहीं भेजा। फिर हमारी सरकार वैटिकन की लल्लो-चप्पो करने में क्यों जुटी है?

दुनिया के किसी भी प्रमुख देश ने - यहाँ तक कि जर्मनी या इटली जैसे ईसाई बाहुल्य देशों ने भी - इतना 'गहरा' शोक नहीं मनाया जैसा कि भारत सरकार और भारत की अंग्रेज़ी मीडिया ने। आखिर भारत धर्मनिरपेक्ष तो ठहरा! दुनिया को वरना पता भी कैसे चलता भारत की धर्मनिरपेक्षता का! फ़्रांस जैसे देश में जहाँ कि लगभग तीन चौथाई आबादी कैथोलिक और नब्बे प्रतिशत से भी अधिक ईसाई मतावलम्बी है, अनेकों शहरों में पौरों और महापौरों ने पेरिस में बैठी फ़्रांसीसी सरकार का राष्ट्रीय शोक का आदेश मानने से इन्कार कर दिया, यह कह कर कि कैथोलिक हम अपने घर में हैं लेकिन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है।

कोई कह के दिखाये ऐसा भारत में - जहाँ पर अभिव्यक्ति की कथित रूप से स्वतंत्रता है। पूरे देश में कठमुल्ले 'तथाकथित धर्मनिरपेक्षाई' छाती पीटना शुरू कर देंगे कि यह आदमी साम्प्रदायिक है, अल्पसँख्यकों के खिलाफ़ है। हालत यहाँ तक आ पहुँची है कि भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तो छोड़ो

शिवसेना, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद वालों तक की जबान नहीं खुलती, जिनके पास वैसे भी इस मामले में खोने को कुछ भी नहीं है। नरेंद्र मोदी तक को कोई बयान देने की ज़रूरत दिखाई नहीं दी।

लेकिन सवाल यह नहीं है कि किसी शंकराचार्य के देहावसान पर राष्ट्रीय शोक होना चाहिये! बल्कि सवाल यह है कि किसी भी धर्मगुरु की मृत्यु पर राष्ट्रीय शोक नहीं होना चाहिये। क्योंकि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में धर्म एक व्यक्तिगत, निजी मामला है। उसका कोई लेना-देना देश की राजनैतिक व्यवस्था से नहीं है। समय आ गया है जब भारत में सच्ची धर्मनिरपेक्षता आये। व्यक्ति को व्यक्ति और भारतीय को भारतीय समझा जाये न कि मुस्लिम, हिंदू, ईसाई या सिख।

आज कांग्रेस माँग कर रही है कि मुसलमानों और ईसाइयों को नौकरियों में आरक्षण मिलना चाहिये। और यही लोग अपने को धर्मनिरपेक्ष भी कहते हैं! बिना कोई शर्म महसूस किये। रामविलास पासवान जैसे लोग हल्ला मचा रहे हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कोई मुसलमान होना चाहिये। और कोई आपत्ति भी नहीं करता। एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र में बजाय यह कहने के कि मुख्यमंत्री वह बने जिसको जनता पसंद करे, क्षुद्र स्वार्थों में पड़े राजनेता लोगों को धर्म के नाम पर पद दिला रहे हैं। यदि एक व्यक्ति मुझे सिर्फ़ इसलिये नौकरी देता है कि मैं मुस्लिम, हिंदू या ईसाई हूँ और एक दूसरा व्यक्ति मुझे सिर्फ़ इसलिये नौकरी नहीं देता क्योंकि मैं मुस्लिम, हिंदू या ईसाई हूँ, तो इन दोनों व्यक्तियों में क्या फ़र्क है? यह दोनों ही साम्प्रदायिक हैं।

इसलिये हमारे सारे स्वघोषित और तथाकथित धर्मनिरपेक्षी सिर्फ़ छद्म धर्मनिरपेक्षी हैं, जिनको या तो अपनी छवि में रुचि है या जिन्हें वोट चाहिये। वरना क्या वजह हो सकती है कि एक हिंदू बहुसंख्यक धर्मनिरपेक्ष देश में ईसाई धर्मगुरुओं की मृत्यु पर राष्ट्रीय शोक मनाया जाता है, लेकिन शंकराचार्य की मृत्यु पर नहीं। भारत का नाम दुनिया में विख्यात करने वाले, मौलिक विचारक ओशो रजनीश की मृत्यु पर नहीं। जहाँ बहुसँख्यक हिंदुओं के धर्मगुरु शंकराचार्य को हिंदुओं के सबसे बड़े त्यौहार दीवाली के दिन गिरफ़्तार करने में किसी को कोई संकोच नहीं होता। यदि शंकराचार्य ने कोई अपराध किया है, तो निःसंदेह उन्हें वही सज़ा मिलनी चाहिये, जो किसी आम नागरिक को मिलती।

मगर अंत में एक सवाल : क्या भारत सरकार या तमिलनाडु सरकार ने ऐसी ही परिस्थितियों में एक मामूली से पादरी को भी क्रिसमस के दिन या किसी इमाम बुखारी को ईद के दिन गिरफ़्तार करने की हिम्मत दर्शायी होती? इस सवाल का जवाब देने की ज़रूरत मेरी समझ से नहीं है - उत्तर स्पष्ट ही है।

कहते हैं न : अँधेर नगरी, चौपट राजा ...

© 2005 IndiaWorld on the Net. All rights reserved.
The article may be reproduced freely subject to following conditions: i) The article can not be edited or modified without written permission from the author; ii) The article can only be reproduced in whole; iii) The author and the copyright holder are to be mentioned clearly and a link to IndiaWorld on the Net (http://www.india-world.net) is provided; and iv) This copyright notice is attached with the reproduced copy.